प्रदेश में 8000 निजी स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु

परिवहन विभाग की कार्रवाई से नाराज हुए बस संचालक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग हाल में कई स्लीपर में आग लगने और दुर्घटना को देखते हुए निजी स्लीपर बसों के खिलाफ विशेष चलाया है। राजस्थान परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से बौखलाए निजी स्लीपर बस संचालकों ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी। जिससे करीब आठ हजार निजी स्लीपर बसों के पहिए थम गए। जिसके चलते करीब 3 लाख सवारियों को परेशानी का सामना करना पडा। जयपुर समेंत जोधपुर और कोटा समेत कई जिलों में निजी 'स्लीपर' बसें शुक्रवार को नहीं चलीं।

शुक्रवार को ट्रेवल्स एजेंसियों ने निजी बसों की बुकिंग रद्द कर दी। जिसके बाद सवारियां रोजवेज बस और ट्रेनों की ओर दौडते नजर आए। वहीं राजस्थान परिवहन विभाग ने यात्रियों की बढ़ती भीड और निजी स्लीपर बसों को अनिश्चितकालीन हडताल को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था कर ली है।

ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर्स एसोसिएशन' की जोधपुर इकाई के अध्यक्ष जफर खान का आरोप है कि परिवहन विभाग तानाशाही ओर मनमाने तरीके से निजी बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और उसने परमिट के उल्लंघन के आरोप में कई बसों को जब्त कर लिया है।

प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरर्स की हड़ताल के कारण सिंधी कैंप पर खड़ी स्लीपर बसें।

जोधपुर में लगभग 500 बसें चल नहीं रहीं। परिवहन विभाग ने परमिट के उल्लंघन पर मनमाने जुर्माने लगाए हैं। जिससे बस संचालकों में रोष है।

अध्यक्ष जफर खान बताया कि परिवहन विभाग ने 'स्लीपर' बसों में आपातकालीन निकासी द्वार न होने जैसे बदलावों पर आपत्ति जताई है। ऐसे में 'हम आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए हमें समय चाहिए।

विभाग ने उन बस बॉडी सेंटरों को भी सील कर दिया है जहां बसों में बदलाव किए जाते हैं। इसलिए अब हमें आवश्यक बदलाव करवाने में समस्या आ रही है।

परमिट जारी किए जा चुके हैं और उन्हीं बसों की फिटनेस जारी भी की चुकी है, लेकिन अब विभाग जुर्माना लगा रहा है। विभाग को अपने उन अधिकारियों और निरीक्षकों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने बसों को फिटनेस में पास किया है।

जयपुर में निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हडताल अनिश्चितकालीन है। एक अन्य प्रतिनिधि ने कहा कि राज्य में लगभग 8 हजार निजी 'स्लीपर' बसें हैं और उदयपुर एवं भीलवाड़ा को छोड़कर सभी जिलों के निजी बस संघों ने अपना समर्थन दिया है।

- जयपुर, जोधपुर और कोटा समेत कई जिलों में निजी 'स्लीपर' बसें शुक्रवार को नहीं चलीं, करीब 3 लाख सवारियां परेशान हुईं
- बताया जा रहा है कि उदयपुर एवं भीलवाड़ा को छोड़कर सभी जिलों के निजी बस संघों ने अपना समर्थन दिया है।

अभियान से बौखलाए निजी स्लीपर बस संचालक

गत दिनों पहले जैसलमेर में एक 'स्लीपर' बस में आग लगने से कई लोग जिंदा जल गए थे। बस में आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी। बस में कोई आपातकालीन निकासी द्वार नहीं था। घटना के बाद, परिवहन विभाग ने अवैध बस संरचना में बदलाव और परमिट मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ गहन जांच अभियान शुरू किया।

प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को मिलेगा बढ़ावा : मुख्यमंत्री

प्रवासी राजस्थानी दिवस से वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का जुड़ाव होगा मजबूत : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली।

- 10 दिसम्बर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा
- कार्यक्रम में एनआरआर ओपन हाउस का होगा आयोजन, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों पर प्रवासी राजस्थानी करेंगे संवाद
- नवंबर माह में पर्यटन प्री-मीट होगी आयोजित

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करने जा रही है। यह वैश्विक प्रवासी राजस्थानी समुदाय का राजस्थान से जुड़ाव को मज़बूत करने के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। साथ ही, इससे प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थान के योगदान को बढावा मिलेगा। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्र में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं एवं उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को जोड़ने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विश्व में अपने ऐतिहासिक किलों, महलों एवं हवेलियों के लिए जाना जाता है। प्रदेश में पर्यटन का हैरिटेज पर्यटन से आगे अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए। इसके लिए प्रदेश में वॉटर एक्टिविटीज सहित अन्य एडवेंचर आधारित टूरिज्म के नए आयामों को विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थान दिवस पर पर्यटन के सेक्टोरल सत्र में टूरिज्म एवं ट्रैवल उद्योग के विशेषज्ञों के साथ ही एडवेंचर आधारित क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। शर्मा ने कहा कि शिक्षा पर आधारित सेक्टोरल सत्र में विशेषज्ञों के साथ ही इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी आमंत्रित किया जाए। साथ ही, स्वास्थ्य सेक्टोरल सत्र के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, फार्मा एवं तकनीकी से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन के सेक्टोरल सत्र में जल अवसंरचनाओं की नवीनतम तकनीकों के साथ ही परंपरागत पद्धितयों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पुरस्कारों में दिए जाने वाले स्मृतिचिन्ह आदि को राजस्थान की लोक कला से जोड़ा जाए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म

जयपुर (कासं)। बस्सी थाना इलाके में क्लासमेट ने अपनी ही नाबालिग सहेली की परिचित से दोस्ती कराई। जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग छात्रा को नशीला जूस पिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। और उसका अश्लील वीडियों बना लिया। जिसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। रोज-रोज की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। गुस्साए परिजनों ने पीड़िता को थाने ले जाकर आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित पिता ने मामला दर्ज कराया है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी प्राईवेट स्कूल में पढती है। क्लासमेंट में अपने परिचित युवक से उसकी जान पहचान कराई थी। जिसके बाद दोनो में आए दिन बातचीत होने लगी। आरोपी ने पीड़ित को मिलने का झांसा देकर बुलाया और ज्यूस में नशीली दवा मिलाकर पिला दी। जिसके बाद आरोपी ने बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियों मोबाइल में बना लिए।

''द चाइना चैलेंज'' सेमिनार में भारत-चीन के संबंधों पर चर्चा

जयपुर। सप्त शक्ति कमान के अधीन में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक ने जयपुर मिलिट्री स्टेशन में ''द चाइना चैलेंज'' विषय पर एक महत्त्वपूर्ण एवं अंतर्दृष्टिपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार में लेफ्टिनेंट जनरल एस.एल. नारसिम्हन (सेवानिवृत्त), राजदूत गौतम बंबावाले, राजदूत सतीश मेहता व जिंदल यूनिवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ प्रोफेसर एलिज़ाबेथ रोच सहित प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया और विषय के विभिन्न आयामों पर विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर अपने महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए।सेमिनार में चीन की तीव्र आर्थिक प्रगति, बढ़ती सैन्य क्षमता, विकसित होती तकनीकी श्रेष्ठता तथा नागरिक एवं रक्षा क्षेत्रों में उसकी बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में भारत-चीन संबंधों की गहन समीक्षा की गई। यह उल्लेख किया गया कि इन कारकों के कारण शक्ति संतुलन को चीन अपनी तरफ झुकना चाहता है। पैनल ने भारत के पडौस तथा विस्तृत भू-राजनीतिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की निर्भरता तथा वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने अपने विश्लेषण को समर्थन देने के लिए ठोस तथ्य एवं आंकड़े प्रस्तुत किए और चीन के विस्तारशील प्रभाव का सामना करने हेतु संभावित रणनीतियों का सुझाव दिया।सेमीनार के अंत में आर्मी कमांडर ने क्षेत्र में हो रहे भू-राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों से अप-टू-डेट रहने की आवश्यकता पर बल दिया, विशेषकर उन बिंदुओं पर जिन पर सेमिनार में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में चीन, पाकिस्तान, कुवैत, नेपाल एवं भूटान में भारत के राजदूत रहे वरिष्ठ अधिकारियों, चीन में भारत के पूर्व डिफेंस प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित शिक्षा विशेषज्ञों जैसे विशिष्ट पैनल के साथ संवाद से संगठन के युवा नेताओं की अंतरराष्ट्रीय विषयों पर समझ और अधिक समृद्ध होगी। उन्होंने सभी वक्ताओं का उनके समय एवं मूल्यवान विचारों के लिए आभार व्यक्त किया।

सप्त शक्ति कमान के अधीन में ज्ञान शक्ति थिंक टैंक की ओर से जयपुर मिलिट्री स्टेशन में ''द चाइना चैलेंज'' विषय पर एक महत्त्वपूर्ण एवं अंतर्दृष्टिपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया।

'डोटासरा को याद आया कांग्रेस का 5 साल का कुशासन'

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा की गई अनर्गल बयानबाजी पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। चतुर्वेदी ने कहा कि लगता है कि डोटासरा को बयान देते वक्त कांग्रेस का पांच साल का कुशासन याद आ गया और वे उस कुशासन की खूबियां गिनाने लग गए। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आम आदमी त्रस्त था। सरकार लगातार डेढ साल तक होटलों में बैठी रही और प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तब लगातार पेपरलीक से युवा परेशान था और मंहगाई से आमजन बेहाल था।

किसानों को 6206 करोड़ रुपये का क्लेम वितरित

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और इसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के बीमित कृषकों को अब तक 6206 करोड़ रुपये का क्लेम वितरित किया जा चुका है।

कृषि मंत्री ने बीमा कंपनी अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमा क्लेम में आ रही समस्याएं, क्लेम सेटलमेंट और पोस्ट हार्वेस्टिंग से संबंधित प्रकरणों का समाधान कर किसानों को जल्द से जल्द बीमा क्लेम उपलब्ध कराया जाये। पारदर्शी फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शत् प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग ऑनलाईन संपादित किये जायें।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य में डीएपी व यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य सरकार भारत सरकार से समन्वय बनाकर अधिकाधिक डीएपी व यूरिया की आपूर्ती के लिए प्रयासरत है। उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं नकली उर्वरकों पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाये जाते हैं।

आय का स्त्रोत नहीं बताने पर दुष्कर्म पीडिता को मुआवजे से इनकार

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा नहीं देने को गलत माना है। अदालत ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट ने आय का स्त्रोत नहीं बताने के आधार पर पीडिता के प्रार्थना पत्र को गलत तरीके से खारिज किया है। इसके साथ ही अदालत ने पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले नए प्रार्थना पत्र को छह सप्ताह में तय करने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो पॉक्सो कोर्ट के बजाए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश दुष्कर्म पीडिता की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने सितंबर, 2023 में सांगानेर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता ने पॉक्सो कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर अंतरिम मुआवजा दिलाने की गुहार की, लेकिन सुनवाई पूरी होने तक प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-3, महानगर प्रथम ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता ने एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर उसे पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत मुआवजा दिलाने की गुहार की।

इस प्रार्थना पत्र को पॉक्सो कोर्ट ने इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया कि उसने अपनी स्कूल फीस आदि का भुगतान करने को लेकर अपनी आय के स्त्रोत की जानकारी नहीं दी। याचिका में पॉक्सो कोर्ट के गत 11 अगस्त के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि नाबालिग पीडिता के पास आय का स्त्रोत कैसे हो सकता है। वहीं मामले में कोर्ट को केवल यह देखना होता है कि पीडिता के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं? ऐसे में याचिकाकर्ता पीडिता को मुआवजा दिलाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पॉक्सो कोर्ट की ओर से पीडिता का प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए छह सप्ताह में मुआवजे पर निर्णय करने को कहा है।

अनाज मंडी में चोरी करने वाले पकड़े

जयपुर। चाकसू थाना पुलिस ने अनाज मंडी में हो रही चोरियों खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को धर-दबोचा है और उनके पास से वारदात में प्रयुक्त दो चौपहिया वाहन भी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने आधा दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण राजर्षि राज ने बताया कि चाकसू थाना इलाके में स्थित अनाज मंडी में सिलसिलेवार 16 दुकानों में नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने अटल बिहारी मीणा उर्फ अजय और महेंद्र सैनी को गिरफ्तार किया है और दोनो ही आरोपित मंडावर जिला दौसा के रहने वाले है।

पूर्व सैनिकों और आश्रितों के कल्याण के लिए सभी सकारात्मक सोच रखते कार्य करें : हरिभाऊ बागड़े

राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों के लिए वृद्धाश्रम, एकीकृत परिसर, बलिदानी योद्धाओं के नाम पर विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों के नामकरण पर समयबद्ध निर्णय पर सैद्धान्तिक स्वीकृति दी

जयपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याण से संबंधित लंबित निर्णयों पर सकारात्मक सोच रखते हुए त्वरित कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए जयपुर में वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत परिसर और विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर किए जाने की समयबद्ध नीति पर सिद्धान्त स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल बागडे शुक्रवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की अठारहवीं बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से संबंधित समस्याओं के प्रभावी और समयबद्ध निराकरण के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़े कार्यों को मन से किया जाए। उन्होंने कहा कि सैनिक देश के लिए लड़ते हैं, उनके कारण ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनके प्रति समाज को कृतज्ञ रहते हुए कार्य करना चाहिए।

बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजोर, मुख्य सचिव सुधांश पंत भी उपस्थित रहे।

बैठक में राज्यपाल बागडे ने राजगढ़, चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना पर सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान की। बैठक में जोधपुर में राईका बाग स्थित सैनिक कल्याण विभाग परिसर में आधुनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत वहां एकीकृत सैनिक परिसर विकसित किए जाने पर भी विचार किया गया। इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने निर्देश दिए कि निर्माण व्यावहारिकता का परीक्षण कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनांतर्गत कार्य किया जाए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड बैठक ली और सूचना पुस्तिका का विमोचन किया।

बैठक में राज्यपाल बागडे ने बलिदानी योद्धाओं के नाम से विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं के नामकरण हेतु एक समान नामकरण नीति अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया।

उन्होनें कहा कि बलिदानी योद्धा के नामकरण के नाम पर समयावधि का निर्धारण कर नीति का प्रावधान किया जाए। इस संबंध में उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शौर्य पदकों से अलंकृत सैनिकों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी किए जाने और अन्य राज्यों में इससे सबंधित हुए निर्णयों के आलोक में व्यावहारिक नीति बनाकर कार्य किए जाने पर सहमति जताई गई।

राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए कि सैनिकों के कल्याण और विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी प्रसार किया जाए। बैठक में राज्य में उपनिवेशन विभाग द्वारा शौर्य पुरस्कार के संदर्भ में पूर्व में समयानुरूप निर्णय नहीं होने से अव्यावहारिक हुए आदेशों के संबंध में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना जारी करने पर भी सहमति जताई गई। राज्यपाल ने वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्रों में अनाधिकृत निवासियों से उसे खाली करवाने और उनके नियमानुसार समुचित उपयोग किए जाने के भी सख्त निर्देश दिए। सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की शिक्षण क्षेत्र में नियुक्ति के अंतर्गत 250 लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की भर्ती के अंतर्गत इस बार 40 पूर्व सैनिक चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को एक ही जगह नियुक्ति की सारी जानकारी मिल जाए, इसकी पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है।

सैनिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ

राज्यपाल बागडे ने सैनिक वेलफेयर पोर्टल का भी शुक्रवार को शुभारंभ किया। पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ऑटोमेशन हेतु यह तैयार किया गया है। इसके तहत विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों को आनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म का लोकार्पण

राज्यपाल बागडे ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म की भी कम्प्यूटर का बटन दबाकर शुरूआत की। राज्य एवं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अब इसके जरिए अद्यतन जानकारी सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध कराई गयी है।

सूचना पुस्तिका का विमोचन

राज्यपाल ने शुक्रवार को ही राजभवन में सैनिक कल्याण विभाग से जुडी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रकाशित सूचना पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

अमलगमेटेड फंड की बैठक

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजभवन में सैनिक कल्याण से जुड़े अमलगमेटेड फंड की बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल श्री बागडे ने बैठक में अमलगमेटेड फंड के 406.46 करोड़ रूपये की आय व्यय का अनुमोदन किया।

इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के अंतर्गत सिपाही से हवलदार रैंक को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि, रक्षा अधिकारी प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए अनुदान राशि और सैनिक विश्राम गृहों के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय राशि से जुड़े सैनिक कल्याण विभाग के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की।